राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, सोमवार, 30 मार्च 2026

वर्ष 14, अंक 337, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

स्टेशन का डीआरएम ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश...03

डेटिंग ऐप के जरिए अपहरण और लूट का खुलासाः 5 आरोपी गिरफ्तार...04

दिल्ली के उत्तम नगर में खुलेआम चल रहा नशा का कारोबार... AAP नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा शासित दिल्ली में एक बार फिर खुलेआम सूखा नशा और अवैध शराब बेचे जाने का खुलासा हुआ है. इस बार यह नशे का कारोबार कैमरे में कैद हुआ है. इसकी कथित वायरल वीडियो को आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर साझा कर भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा है. हालांकि टीवी9 वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के उत्तम नगर में खुलेआम हो रहा नशा कारोबार कैमरे में कैद हो गया, लेकिन इस पर सरकार मौन है. जिस तरह से खुलेआम नशा बिक रहा है, उससे साफ है कि तस्करों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की बात सही साबित हो रही है कि नशा तस्करों को सरकार के लोग छुड़वा देते हैं. चार इंजन की भाजपा सरकार होने के बाद भी पूरी दिल्ली में नशे का

कारोबार खुल्लम-खुल्ला चल रहा है।

सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर भी साधा निशाना

रविवार को एक्स पर नशा बेच रही एक महिला का वीडियो क्लीप साझा कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह एक बड़ा खुलासा है. दिल्ली के उत्तम नगर में गांजा, ड्रग्स और अवैध शराब खुलेआम बिक रही है. उपराज्यपाल कार्यालय को टैग करने के बावजूद वहां से कोई जवाब नहीं आया है. एक मीडिया चैनल की यह महिला रिपोर्टर अपनी जान जोखिम में डाल रही है. असल में यह काम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को करना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इंस्टाग्राम रील बनाने में व्यस्त है, जबकि जमीन पर कोई काम नहीं कर रही है. उधर, दिल्ली के नए उपराज्यपाल साहब अपना प्रचार करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं. वे अपनी वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं. जैसे कि कनॉट प्लेस में लोग उनका अभिवादन कर रहे हों. आम लोग अचानक से यह कैसे पहचान लेते हैं कि वे ही नवनियुक्त उपराज्यपाल हैं? क्या एक उपराज्यपाल का यही काम होता है?

रेखा सरकार पर बोला हमला

आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो लगातार दिल्ली में बढ़ रहे नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठा रही है. पिछले दिनों वजीरपुर में एक व्यक्ति की नशेड़ियों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. इससे आक्रोशित लोगों ने जब भारत नगर थाने का घेराव किया तो तत्कालीन SHO ने कहा कि पुलिस के हाथ बंधे हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस नशा कारोबारियों को पकड़ती है तो सीएम कार्यालय से आदेश आ जाता है और उन्हें छोड़ना पड़ता है. यह वीडियो वायरल होने पर रेखा गुप्ता सीएम पर जमकर हमला बोला था. इसके अलावा, अभी पिछले दिनों ही भाजपा शासित MCD की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा ने खुद चांदनी चौक में अवैध शराब की बिक्री का भंडाफोड़ करते हुए भाजपा की दिल्ली पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया था।

कांग्रेस ने अटकाया रोड़ा, वरना मेरी सरकार में ही बन जाता नोएडा एयरपोर्ट... मायावती का बड़ा दावा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की रूपरेखा और बुनियादी काम उनकी सरकार में ही शुरू हो गए थे, लेकिन केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की वजह से इसमें देरी हुई।

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (28 मार्च) को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया था. जिसको लेकर मायावती ने सवाल खड़े किए हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने एक लंबा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा 'लम्बे इंतज़ार के बाद जेवर में नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा के प्रथम चरण का कल उद्घाटन हुआ, जबकि इसकी रूपरेखा ही नहीं बल्कि इसके सभी ज़रूरी बुनियादी कार्य बीएसपी. की मेरी सरकार में ही शुरू हो गए थे'।

कांग्रेस पर बरसीं मायावती

पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा 'इतना ही नहीं बल्कि उस समय केन्द्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर रोड़ा नहीं अटकाती तो विकास का यह कार्य, यमुना एक्सप्रेसवे आदि की तरह, काफी पहले मेरी सरकार में ही पूरा हो गया होता।

सपा पर भी साधा निशाना

इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने पोस्ट में कहा 'जहां तक सपा सरकार का सवाल है तो इनका ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश की गरीबी और पिछड़ेपन आदि को दूर करने हेतु विकास के ठोस कार्य करने के बजाय राजनीतिक फायदा उठाने में चला गया।

उन्होंने कहा 'ख़ासकर बीएसपी सरकार द्वारा समाज के कमजोर तबकों के हित, कल्याण और उनके उत्थान के लिए गए ऐतिहासिक फैसलों एंव किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को निष्क्रिय बनाने के साथ-साथ बहुजन समाज में जन्में महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान में निर्मित शिक्षण व मेडिकल संस्थानों व ज़िला आदि का नाम बदलने व उनके नाम पर बने स्थलों, स्मारकों, एवं पार्कों आदि की अनदेखी व उपेक्षा करने के नकारात्मक, जातिवादी व राजनीतिक द्वेष में ही ज़्यादातर समय लगी रही, जो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है'।

बीएसपी प्रमुख की जनता से अपील

बीएसपी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वो विरोधी पार्टियों की छलावापूर्ण राजनीति और बहकावे में ना आकर बीएसपी. के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति और सिद्धान्त में विश्वास रखते हुए अपने एंवप्रदेश के विकास हेतु बीएसपी. के आयरन नेतृत्व पर ही भरोसा करें. इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाए हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की अलग से बेंच व उनके लिए अलग से प्रदेश बनाने का सपना ना जाने कब पूरा होगा?

बात नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की करें तो बीते शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में 11,282 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया. उत्तर प्रदेश अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

संक्षिप्त ख़बरें

रोशन नगर ग्राम पंचायत की गौशाला में गोवंशीय पशुओं की दुर्दशा, जिम्मेदार बेखबर

लखीमपुर खीरी। ब्लॉक गोला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रोशन नगर ग्राम पंचायत की गौशाला में गोवंशीय पशुओं की स्थिति

अत्यंत दयनीय बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, गौशाला में न तो पशुओं के लिए पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध है और न ही स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते गोवंशीय पशु भूख-प्यास से तड़पने को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मामले में जिम्मेदार अधिकारी और ग्राम प्रधान एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं। ब्लॉक गोला के वीडियो (ग्राम पंचायत अधिकारी) और ग्राम प्रधान दोनों ही इस स्थिति से अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।सूत्रों के अनुसार, गौशाला के पास ही गोवंशीय पशुओं की सामूहिक कब्रें भी पाई गई हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि पशुओं की लगातार मौत हो रही है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि पशु संरक्षण के दावों पर भी सवाल खड़े करती है।

आपसी विवाद में युवक पर जानलेवा हमला

कानपुर। दिनांक 27.03.2026 को थाना चकेरी क्षेत्र के अहिरवां में आपसी विवाद के चलते एक युवक पर कुछ लोगों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में घायल की तहरीर के आधार पर थाना चकेरी पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। तहरीर में तीन नामजद अभियुक्त दर्शाए गए हैं। घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है तथा प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

मलिहाबाद में दबंग प्रधान पर गंभीर आरोप, हमले की आड़ में रचा झूठा मुकदमा?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद -लखनऊ लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित बिराहिमपुर ग्राम पंचायत के प्रधान रामशंकर एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन पर हुए अज्ञात लोगों द्वारा हमले के मामले में अब खुद प्रधान की भूमिका पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि दबंग छवि वाले प्रधान ने रंजिश के चलते निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि 23 मार्च 2026 की रात करीब 10:30 बजे प्रधान रामशंकर ने अपने ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमले की तहरीर दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद दर्ज कराई गई एफआईआर में कई लोगों को नामजद किया गया, लेकिन अब इनमें शामिल युवक आदित्य प्रताप सिंह व पूर्व प्रधान विमल रावत ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है। आदित्य प्रताप सिंह, निवासी रामपुर बस्ती, थाना मलिहाबाद, का कहना है कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान ने पुरानी रंजिश के चलते उनका नाम झूठे तरीके से एफआईआर में डलवाया है। आदित्य के अनुसार, घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद थे और इसकी पुष्टि उनके मोबाइल फोन की लोकेशन तथा इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से की जा सकती है। उन्होंने पुलिस से इन साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की है। व प्रधान के भी कॉल डिटेल्स, व हमले वाले स्थान के आस पास लगे सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की मांग की है।

वहीं पूर्व प्रधान विमल रावत का भी नाम FIR में दर्ज है, उन्होंने ने भी कहा है कि जिस समय दबंग प्रधान रामशंकर हमले की बात कह रहा है तब वह अपने घर पर मौजूद थे उनका कहना है कि पुलिस उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करे, ताकि यह साफ हो सके कि असल में इस घटना से उनका कोई ताल्लुक नहीं है स्थानीय लोगों के बीच भी यह चर्चा है कि प्रधान की दबंगई के चलते कई बार विवाद की स्थिति बनती रही है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विरोधियों को फंसाने की कोशिश की है।

आदित्य ने यह भी कहा कि इससे पहले भी उनका नाम इसी तरह अन्य मामलों में गलत तरीके से जोड़ा गया था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह उच्च अधिकारियों और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सम्बंधित प्रकरण में हमारे संवाददाता द्वारा एडीसीपी उत्तरी ऋषभ रुनवाल से पूरे मामले में बात की गई उन्होंने जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

'शादीशुदा पुरुष का बालिग के साथ लिव-इन में रहना जुर्म नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा और साफ फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन में रहता है, तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट का कहना है कि नैतिकता क्या कहती है और कानून क्या कहता है, ये दोनों बातें अलग हैं. अगर कोई कानून नहीं टूटा है, तो सिर्फ सामाजिक सोच के आधार पर किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. कोर्ट ने अगले आदेश तक याचिकाकर्ता जोड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस को उन्हें सुरक्षा देने का आदेश दिया है।

यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिविजन बेंच ने याचिकाकर्ता अनामिका और नेत्रपाल की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया गया है कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इसके साथ ही, कोर्ट ने महिला (अनामिका) के घरवालों को भी कड़ी चेतावनी दी है. परिवार का कोई भी सदस्य इस जोड़े को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा. वे न तो उनके घर में घुसेंगे और न ही फोन, मैसेज या किसी तीसरे बंदे के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे।

सुरक्षा के मामले में कोर्ट ने शाहजहांपुर के पुलिस कप्तान (SP) को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि जोड़े की हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 'शक्ति वाहिनी' वाले केस में पहले ही साफ नियम बनाए हुए हैं। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया है कि वो इस आदेश की सूचना पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर और थाना प्रभारी पुलिस थाना जैतीपुर को दोनों को ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के माध्यम से अगले 24 घंटों के अंदर भेज दें. अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

कमजोर बच्चों की पहचान के लिए दिल्ली सरकार चलाएगी विशेष अभियान, 1098 हेल्पलाइन नंबर के प्रति बढ़ेगी जागरूकता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार अप्रैल में पूरे शहर में एक अभियान चलाएगी, ताकि कमजोर बच्चों की पहचान की जा सके, उन्हें वेलफेयर स्कीम से जोड़ा जा सके और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में जागरुकता बढ़ाई जा सके। महिला और बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी), नान-प्राफिट संस्थाओं के साथ मिलकर, झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में रहने वालों को मौजूद सपोर्ट सिस्टम के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाएगा।

विभाग की जानकारी के अनुसार 2023 में चाइल्ड हेल्पलाइन के इमरजेंसी नंबर 112 के साथ मर्ज होने के बाद, 2023 और 2025 के बीच 2,18,699 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 14,684 मामले डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स (डीसीपीयूए) को भेजी गईं। इनमें बच्चों के साथ गलत व्यवहार की 4,249, काउंसलिंग सपोर्ट की 1,951, लापता बच्चों से संबंधित 1,984 और बच्चों और परिवार से जुड़े मामले 1,114) शामिल थे।

बेहजम ब्लॉक क्षेत्र में उखड़ी सड़क और गहरे गड्ढों में हिचकोले खा रहे वाहन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नीमगांव खीरी। लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत बेहजम ब्लॉक क्षेत्र में सड़कों के हालात खराब हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है,रखरखाव में लापरवाही व भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बदहाल हो गई हैं। कदम-कदम पर बने जानलेवा गड्ढे और उसमें भरा बारिश का पानी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। तरुण मित्र संवाददाता ने शनिवार को बेहजम विकास खंड के पैला-नगरा मार्ग व,नीमगांव से देवरी गांव व नीमगांव कस्बे से होते हुए सेहरुआ कस्बें तक व गुलौला से नीमगांव जानें वाला मार्ग की पड़ताल की। ये सभी सड़कें बदतर हालत में हैं।

ब्लाक मुख्यालय को जोड़ने वाली नीमगांव कस्बे-देवरी सड़क वर्षो से उपेक्षा का शिकार है। करीब 2 किमी लंबी सड़क का निर्माण कई वर्षो पहले मंडी समिति के द्वारा कराया गया था,यह मार्ग कई वर्षो से जर्जर है और सड़क पर जानलेवा गड्ढे है,कई वर्षो से ग्रामीण मार्ग के निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं,लेकिन किसी न इस और ध्यान नहीं दिया।

क्षेत्र के हरिनाम सिंह, लाल मोहम्मद, अंकित दीक्षित, पंकज पांडे, आदि ने कहा कि नीमगांव कस्बे के चमन चौराहा से होते हुए प्रतापपुर होते हुए कैमहरा कस्बें से जोड़ने वाला मार्ग भी जर्जर हालत में और इस मार्ग पर जानलेवा गड्ढे है। साथ ही पैला, सुजौलापुर, देवरी, मूड़ा बुजुर्ग, प्रतापपुर, सुनौरा, जैतापुर आदि गांव को भी जोड़ती है। वर्तमान में पूरी सड़क जर्जर हो चुकी है। संज्ञान में लाने के बाद भी विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

बड़ोखर पीडब्ल्यूडी की सड़क निर्माण मे घटिया सामग्री से बनाने का आरोप

कोरांव प्रयागराज। यमुनापार के बड़ोखर मे मेन रोड से बाजार तक पीडब्ल्यूडी पक्की सड़क निर्माण कार्य कराया गया है स्थानीय लोगों ने बताया कि यह सड़क निर्माण बहुत ही घटिया सामग्री से कराया जा रहा है जो महीने से पहले ही ध्वस्त हो जायेगी युवा समाजसेवी और भावी जिला पंचायत सदस्य प्रमोद तिवारी का कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है बहुत ही घटिया सामग्री से कराया गया है सड़क मे भारी भ्रष्टाचार हुआ है मानक के आधार पर सड़क नही बनाई गई है जिसके कारण स्थानीय लोगों मे भारी आक्रोश व्याप्त है।

सीतापुर शिक्षण संस्थान में परीक्षक से अभद्रता व मारपीट का आरोप, LUACTA सख्त; प्रायोगिक परीक्षाएं निरस्त

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

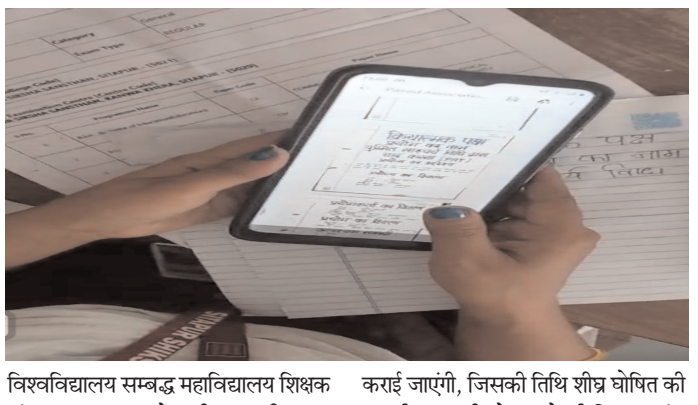

सीतापुर जनपद सीतापुर के एक शिक्षण संस्थान में बी.एड. प्रायोगिक परीक्षा के दौरान गंभीर अनियमितताओं और परीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षक डॉ. नितिन पांडेय जब परीक्षा सम्पन्न कराने संस्थान पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि कुछ छात्र मोबाइल, व्हाट्सएप और टैबलेट के माध्यम से नकल कर रहे हैं। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से डॉ. पांडेय ने इस स्थिति का वीडियो बनाना शुरू किया। आरोप है कि इसी बात से आक्रोशित होकर संस्थान प्रबंधन और कुछ शिक्षकों ने उनके साथ अभद्रता की, मारपीट की तथा उन्हें धमकाया। घटना के दौरान उनका मोबाइल फोन भी छीन लिए जाने की बात सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम को परीक्षक के साथ गंभीर हादसे के रूप में देखा जा रहा है, जिसने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ (LUACTA) ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। संघ ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षकों की गरिमा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी क्रम में 27 मार्च 2026 को आयोजित परीक्षा समिति की बैठक में अहम निर्णय लिए गए। समिति ने 23 मार्च 2026 को संबंधित शिक्षण संस्थान में आयोजित सभी बी.एड. प्रायोगिक परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। अब ये परीक्षाएं आरएमपी महाविद्यालय, सीतापुर में पुनः आयोजित कराई जाएंगी, जिसकी तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। जांच रिपोर्ट आने तक संबंधित शिक्षण संस्थान को सभी प्रकार के परीक्षा कार्यों से वंचित रखने का निर्णय लिया गया है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि यदि मामले में शीघ्र न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई, तो शिक्षक संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि शिक्षा व्यवस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए दोषियों को हर हाल में दंडित किया जाना आवश्यक है।

जनता पर आए न तपिश सरकार की बड़ी कोशिश और जनकल्याण की दिशा में मजबूत कदम

पश्चिम एशिया में जारी महासंग्राम ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने अनेक देशों के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक आम नागरिक महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ झेलने को मजबूर हैं। कई देशों में कीमतों में भारी वृद्धि के कारण महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और लोगों के दैनिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे कठिन समय में भारत सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता जनता को राहत देना है न कि बोझ बढ़ाना।

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने उत्पाद कर में प्रति लीटर दस रुपये की कटौती का बड़ा फैसला किया है। यह कदम केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि एक संवेदनशील शासन दृष्टिकोण का प्रतीक है। जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें सत्तर डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर एक सौ बाईस डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं तब इस तरह की राहत देना आसान नहीं होता। इसके बावजूद सरकार ने यह जोखिम उठाया ताकि आम आदमी पर महंगाई की मार न पड़े। यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि सरकार का अभिगम पूरी तरह जनतालक्षी है। सरकार यह समझती है कि ईंधन की कीमतों का सीधा असर हर वस्तु और सेवा पर पड़ता है। यदि पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो परिवहन लागत बढ़ेगी और उसके साथ ही खाद्यान्न से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी। इस स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने अपने राजस्व में कटौती सहने का रास्ता चुना। अनुमान है कि इस फैसले से सरकार को हर पंद्रह दिनों में हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। इसके बावजूद यह निर्णय लिया गया क्योंकि प्राथमिकता जनता की राहत है।

सरकार ने केवल कर में कटौती ही नहीं की बल्कि ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को बढ़ाकर सत्तर प्रतिशत तक करने का निर्णय इसका एक बड़ा उदाहरण है। इससे उद्योगों को आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध होगी और उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशेष रूप से स्टील ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे श्रम आधारित उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर सुरक्षित रहेंगे और आर्थिक गतिविधियां सुचारु रूप से चलती रहेंगी।

आज जब दुनिया के कई देश ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं तब भारत में पर्याप्त भंडार बनाए रखना भी सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है। देश के पास साठ दिनों से अधिक का पेट्रोलियम भंडार उपलब्ध है। यह स्थिति आम नागरिकों में विश्वास पैदा करती है और घबराहट को रोकती है। सरकार ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों को अनावश्यक रूप से भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है।

इस पूरे परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है और वह है अफवाहों पर नियंत्रण। संकट के समय अफवाहें स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। कुछ स्थानों पर पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखी गई लेकिन सरकार ने तुरंत स्पष्ट किया कि यह घबराहट बेबुनियाद है। ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार का लॉकडाउन या प्रतिबंध लागू करने की कोई योजना नहीं है। इस तरह के स्पष्ट संदेश से जनता में विश्वास कायम हुआ है।

सरकार के इस दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उसने केवल वर्तमान संकट को संभालने पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि भविष्य की संभावित चुनौतियों के लिए भी तैयारी की है। निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय इसी दिशा में एक कदम है। इससे देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और घरेलू बाजार में स्थिरता बनी रहेगी। यह निर्णय उद्योग और उपभोक्ता दोनों के हितों को संतुलित करने का प्रयास है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने इस संकट को एक अवसर के रूप में लिया है जिसमें वह अपनी नीतियों के माध्यम से जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर सके। जब पूरी दुनिया महंगाई और अस्थिरता से जूझ रही है तब भारत ने एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहां सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि आम नागरिक को कम से कम परेशानी हो और आर्थिक गतिविधियां भी बाधित न हों। इस नीति का सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। जब जनता को यह महसूस होता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है तब समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लोग अधिक जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करते हैं और संकट का सामना करने में सहयोग करते हैं। यही कारण है कि सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें और अनावश्यक घबराहट से बचें। अंततः यह स्पष्ट होता है कि यह निर्णय केवल आर्थिक गणना का परिणाम नहीं है बल्कि एक व्यापक सोच का हिस्सा है जिसमें जनता की भलाई सर्वोपरि है। सरकार ने यह दिखाया है कि कठिन परिस्थितियों में भी जनहित को प्राथमिकता दी जा सकती है। भले ही इससे सरकारी खजाने पर दबाव पड़े लेकिन यदि इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलती है तो यह एक सार्थक और न्यायसंगत निर्णय है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह संदेश दिया है कि मजबूत नेतृत्व और संवेदनशील नीति निर्माण के माध्यम से किसी भी वैश्विक संकट का प्रभाव कम किया जा सकता है। भारत ने यह साबित किया है कि वह न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखता है बल्कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी स्थिरता का उदाहरण बन सकता है। जनता पर आए न तपिश यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त संकल्प है जिसे सरकार अपने निर्णयों के माध्यम से साकार कर रही है।

कांतिलाल मांडोत

संपादकीय

अफ़वाहों का बाज़ार: सरकार, विपक्ष और समाज की ज़िम्मेदारी

वर्तमान में संपूर्ण विश्व भू-राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध की विभीषिकाओं और आर्थिक अनिश्चितताओं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस वैश्विक उथल-पुथल के मूल में रूस-यूक्रेन महासमर, ईरान-अमेरिका,इजरायल के मध्य गहराता संघर्ष, अमेरिका की संरक्षणवादी टैरिफ नीतियां तथा तीव्र होती वैश्विक गुटबाजी जैसे कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी नजर आते हैं।?इन द्वंद्वों के परिणामस्वरूप ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक तंत्र, कूटनीतिक संतुलन और वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिरता जैसे विषय आज राष्ट्रों के लिए अत्यंत चिंताजनक बन गए हैं। जहाँ कुछ राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं, वहीं भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसके परोक्ष आर्थिक दुष्प्रभावों का सामना करने को विवश हैं। विशेष रूप से तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और कीमतों की अस्थिरता को नियंत्रित रखना विकसित से लेकर अविकसित देशों तक के लिए एक चुनौती बन गया है।?ऐसे संकटकाल में, भारत जैसे विशाल एवं संवेदनशील लोकतंत्र के समक्ष न केवल ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को अक्षुण्ण बनाए रखने और मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने की चुनौती है, बल्कि आंतरिक स्तर पर प्रसारित होने वाली भ्रामक सूचनाओं और अफ़वाहों के विरुद्ध जनमानस को सचेत व जागरूक करना भी एक अनिवार्य दायित्व बन गया है।

आज सोशल मीडिया और अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से भ्रामक खबरें तीव्र गति से फैल रही हैं। कहीं फिर से लॉकडाउन लगने का डर दिखाया जा रहा है, तो कहीं ईंधन की भारी कमी की आशंका जताई जा रही है, तो कुछ तेल और गैस की कीमतों के साथ रोजमर्रा के आवश्यक सामान जैसे किराना आदि के दामों में भारी वृद्धि होने का डर फैलाया जा रहा है।कुछ तत्व तो विश्व युद्ध या परमाणु हमले का भय दिखाकर जनता को आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की अनुचित सलाह दे रहे हैं। ऐसी अपुष्ट सूचनाएं न केवल सामाजिक तनाव बढ़ाती हैं, बल्कि आर्थिक असंतुलन और 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में खरीदारी) को भी जन्म देती हैं।इसका सबसे घातक परिणाम यह होता है कि बाज़ार में कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है, जिसका लाभ जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले तत्व उठाते हैं।हाल ही में गैस की कालाबाजारी के कुछ मामले पकड़े भी गए हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अफ़वाहें केवल सूचना का संकट नहीं, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

डिजिटल क्रांति ने सूचना के प्रसार को पंख दे दिए हैं, लेकिन इसी के साथ अफ़वाहों की गति भी बढ़ी है। कुछ राष्ट्रविरोधी तत्व पुराने वीडियो को वर्तमान संघर्षों से जोड़कर या विदेशी घटनाओं को भारत का बताकर साझा करते हैं। कुछ लोग तो पड़ोसी और अन्य विश्व के देशों में तेल और गैस की किल्लत और दामों में वृद्धि को दिखा कर भ्रम फैला रहे हैं कि भारत में भी ऐसे ही हालात निर्मित होने वाले हैं।ऐसी भ्रामक स्थिति में आम नागरिक के लिए सत्य और असत्य के बीच की धुंधली रेखा को पहचानना कठिन हो जाता है, जिससे समाज में अविश्वास का माहौल पनपता है। अतः सरकार का दायित्व हो जाता है कि वह ऊर्जा आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और विदेश नीति पर निरंतर पारदर्शिता और जनता से संवाद बना कर रखे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय तथा सभी राजनीतिक दलों के साथ संवाद इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है, जैसा कि हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह के प्रयास किए गए हैं। इसी दिशा में सभी राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित कर विचार विमर्श किया गया तथा वस्तु स्थिति पर राज्य सरकारों की आगामी रणनीति कैसी होनी चाहिए पर विचार किया गया । सब का विश्वास अर्जित करने की दिशा में इसे अच्छा प्रयास कहा जा सकता है।

विपरीत स्थितियों में विपक्षी दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा या वैश्विक संकट के समय विपक्ष को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्हें ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए जो जनता में भ्रम और असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। रचनात्मक सुझाव देना और संकट के समय सरकार के साथ खड़े होकर जनता का मनोबल बढ़ाना ही एक परिपक्व विपक्ष की पहचान है। नीतियों का विरोध वैचारिक हो सकता है, लेकिन वह राष्ट्र के मनोबल को कमजोर करने वाला कदापि नहीं होना चाहिए।हर विपक्ष दलों के नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर एक बार देखने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा संकट की इस घड़ी में दिया गया वक्तव्य क्या देश हित में उचित है?

मैं तो इस समय यही कहना चाहूंगा कि वैश्विक संकट की घड़ी में सरकार, विपक्ष और जनता की आवाज़ एक होनी चाहिए। जब देश के भीतर एकता होती है, तो बाहरी चुनौतियों का सामना करना सरल हो जाता है। समाज को भी यह समझना होगा कि बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी पर विश्वास करना और साझा करना अफ़वाह को बढ़ावा देना है। आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना और 'फैक्ट-चेक' की संस्कृति विकसित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मीडिया को भी सनसनीखेज खबरों के बजाय तथ्यपरक पत्रकारिता पर ध्यान देना चाहिए।अफ़वाहों का संक्रमण तभी रुकेगा जब सरकार पारदर्शी हो, विपक्ष उत्तरदायी हो और समाज जागरूक हो। हमें डर और भ्रम से नहीं, बल्कि तथ्य और संयम के साथ आगे बढ़ना होगा ।

डॉ. मनमोहन प्रकाश

तीन देशों की सनक से पैदा वैश्विक आर्थिक, सामरिक संकट

संभावित परमाणु युद्ध महा - विनाशक होने की संभावना।

जैसी की आशंका दिखाई दे रही है ईरान की भयभीत आम जनता एवं वर्तमान में बचे हुए ईरानी टॉप लीडर्स कि यह पुरजोर मांग है कि ईरान के पास जितना परमाणु ईंधन अमेरिका के आक्रमण से जमीन में धंसा हुआ बचा है, उससे कम से कम 10 बड़े परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और इस परमाणु बम को बनाने के लिए ईरान प्रशासन पर पूरा दबाव डाला जारहा है। यह हालत इसलिए पैदा हुए हैं की इस त्रिकोणीय युद्ध में ईरान को बहुत बड़ी संख्या में जनहानि और बड़ी मात्रा में आर्थिक क्षति पहुंची है, ईरानके हजारों लोग मारें गए और 25000 से ज्यादा बड़ी-बड़ी बिल्डिंग,स्कूल और हॉस्पिटल ध्वस्त हुए हैं, ईरान में शिया सुन्नी झगड़ा भी अपने चरम पर है। सुन्नी लोग अब शासन का तख्ता पलटने के प्रयास में लगे हुए हैं। अमेरिका तथा इजरायल युद्ध से ईरान में हुए इस नुकसान को पूरा करने में ईरान को 15 से 20 साल लग सकते हैं। ईरान की सरकार और उनकी जनता के बीच जिस तरह से करो या मरो की स्थिति बनी है, जिसके परिणाम स्वरुप वहां की जनता और नेता यह चाहते हैं कि परमाणु बम बनाना तथा ईरान इजरायल और उसके सहयोगी देशों पर परमाणु हमला करना ही उनके अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम और सम्यक विकल्प हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका इजरायल और ईरान यदि परमाणु संघर्ष में बदल सकता है। इसके परिणाम में यह परमाणु युद्ध मानव इतिहास के उन भयावह क्षणों से भी अधिक विनाशकारी होगा, जिनकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु हमलों से हुई थी। हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट की घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इसके तीन दिन बाद, नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट 9 अगस्त 1945 को हुआ, जब अमेरिका ने ही नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। यह घटनाएँ द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका और जापान के बीच हुए युद्ध का हिस्सा थीं। गौर तलब है कि उसे समय के परमाणु बम सीमित शक्ति के थे और उनका प्रभाव मुख्यतः स्थानीय स्तर पर केंद्रित रहा था, जबकि आज के परमाणु हथियार अत्यधिक उन्नत, बहु-मेगाटन क्षमता वाले और दूरगामी प्रभाव वाले विकसित हो चुके हैं। आधुनिक परमाणु युद्ध केवल एक शहर या देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका प्रभाव विश्व के हर देश के स्तर पर फैलेगा, यदि ईरान परमाणु हथियार का उपयोग करता है या उस पर परमाणु हमला होता है तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रभाव मध्य पूर्व क्षेत्र में दिखाई देगा, जिसमें इज़रायल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है वह पूरी तरह विनाशकारी स्थिति में पहुंच सकता है। वहां जनसंख्या का बड़ा हिस्सा तुरंत प्रभावित होगा और बुनियादी ढांचा समाप्त हो सकता है। इसके साथ ही सऊदी अरब में रेडियोधर्मी कण पहुंचने की आशंका होगी जिससे वहां के तेल भंडार, जल स्त्रोत और जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। इराक और सीरिया जैसे पड़ोसी देश जो पहले से अस्थिर हैं, यहां परमाणु विकिरण के कारण मानवीय संकट और भी गहरा जाएगा, तुर्की जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, वह रेडियोधर्मी बादलों के प्रभाव से कृषि और स्वास्थ्य संकट का सामना कर सकता है। इसके आगे यह विकिरण वायुमंडलीय धाराओं के माध्यम से यूरोप के देशों जैसे ग्रीस, इटली और जर्मनी तक फैल सकता है, जहां कैंसर, श्वसन रोग और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ने की संभावना होगी। यदि संघर्ष बृहद रूप लेता है और अमेरिका तथा रूस जैसे परमाणु शक्तिशाली देश इसमें शामिल होते हैं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी क्योंकि तब यह सीमित युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक परमाणु टकराव का रूप ले सकता है। भारत और पाकिस्तान भी इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से अछूते नहीं रहेंगे, यहां पर मानसूनी चक्र में बदलाव, तापमान में गिरावट और कृषि उत्पादन में भारी कमी देखने को मिल सकती है जिसे 'न्यूक्लियर विंटर' कहा जाता है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश धूल और धुएं के कारण धरती तक नहीं पहुंच पाएगा जिससे वैश्विक खाद्य संकट उत्पन्न होगा, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को भी आपूर्ति श्रृंखला टूटने, व्यापार बाधित होने और जनस्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ेगा। अफ्रीका के देश जैसे मिस्त्र और नाइजीरिया खाद्य आयात पर निर्भर हैं, वहां अकाल और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं दक्षिण अमेरिका के देश जैसे ब्राज़ील में भी जलवायु परिवर्तन और कृषि हानि देखने को मिल सकती है, इस पूरे परिदृश्य में एक बड़ा अंतर यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय केवल दो बम गिराए गए थे और उनका प्रभाव सीमित समय और स्थान में रहा, जबकि आज के परमाणु हथियारों की संख्या हजारों में है और उनकी मारक क्षमता कई गुना अधिक है, आधुनिक मिसाइल तकनीक जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ ही मिनटों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक परमाणु हथियार पहुंचा सकती है, इसके अलावा आज की दुनिया अधिक परस्पर जुड़ी हुई है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, संचार प्रणाली, इंटरनेट और आपूर्ति श्रृंखलाएं एक-दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए किसी एक क्षेत्र में परमाणु विस्फोट का प्रभाव पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी, तकनीकी ठहराव और सामाजिक अराजकता के रूप में दिखाई दे सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रेडियोधर्मी विकिरण केवल तत्काल मृत्यु ही नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियां जैसे कैंसर, जन्म दोष और मानसिक विकार पैदा करेगा, पर्यावरणीय दृष्टि से नदियां, महासागर और मिट्टी प्रदूषित हो जाएंगे जिससे जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।यदि हम तुलना करें तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों ने लाखों लोगों की जान ली थी, लेकिन आज का परमाणु युद्ध अरबों लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। यह अनुमानित और विशेष रूप से संभावित अमेरिका-इज़रायल-ईरान परमाणु संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक विनाशक आपदा होगा, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग हर देश प्रभावित होगा, और मानव सभ्यता को सदियों पीछे धकेल सकता है। इसलिए यह केवल सैन्य या राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मानवता के अस्तित्व का प्रश्न है।जिसे कूटनीति, संयम और वैश्विक सहयोग के माध्यम से युद्ध विराम करके ही टाला जा सकता है।

संजीव ठाकुर

धोखेबाज पाकिस्तान की कुंडली

पश्चिम एशिया में संकट पर केन्द्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने देश में पर्याप्त तेल और गैस भंडार होने और स्थिति नियंत्रण में होने का भरोसा दिया। विपक्षी दलों ने संकट के इस दौर में सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की लेकिन साथ ही उसने अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका पर चिंता जताई। विपक्ष की चिंताओं का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा व्यंग्य कसते हुए कहा कि भारत वैश्विक भूराजनीति में 'दलाल राष्ट्र' के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की नौटंकी नई नहीं है और यह 1981 से जारी है। अमेरिका वर्षों से तेहरान के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए इस्लामाबाद का इस्तेमाल एक चैनल के रूप में करता आया है। विदेश मंत्री की यह ?टिप्पणियां ऐसी खबरों के बाद आई हैं जब पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के बीच संदेशों को सक्रिय रूप से पहुंचाने की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका ने ईरान को 15 सूत्री प्रस्ताव भी पाकिस्तान के माध्यम से ही भेजा है। यद्यपि ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्री प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के इतिहास के पन्ने पलटें तो उसका पूरा इतिहास धोखे और दलाली से भरा हुआ है। पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनने के बाद से ही दलाली करता आया है। जब-जब पाकिस्तान ने शांति दूत का चोला पहना तब-तब दुनिया ने खून-खराबा और विश्वासघात देखा है।

कई रक्षा विशेषज्ञों ने समय-समय पर पाकिस्तान के दोगलेपन की ऐसी कहानियां सुनाई हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान पर कोई भी देश भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान ने हमेशा ही अपने आवाम को धोखे में रखा और उसके हुक्मरानों ने अपने ही देश को जमकर लूटा। उसके धोखे का शिकार पड़ोसी देश भी हुए। 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति बुश पर युद्ध उन्माद छाया हुआ था और अमेरिका ने पाकिस्तान को तालिबान से अलग न होने पर उसे पत्थर युग में वापिस भेजने की धमकी दी थी, तब तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने यू-टर्न लेकर अमेरिका की गोद में बैठना बेहतर समझा था। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान को अपना साथी बना लिया। यह कितना हास्यास्पद था कि एक जेहादी देश को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में आगे कर दिया गया। जबकि अमेरिका जानता था कि ट्विन टॉवर पर हमला करने वाले आतंकवादियों में कुछ को ट्रेनिंग भी पाकिस्तान ने ही दी थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया और आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान पर डॉलरों की बरसात कर दी। पाकिस्तान ने एक तरफ अमेरिकी डॉलरों का इस्तेमाल आतंकवाद को सींचने के ?लिए किया तो दूसरी तरफ अमेरिका को धोखे में रखकर तालिबान को संरक्षण दिया। अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान को मरघट में बदल सकता था, पर अमेरिका को लगता था कि अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन और अन्य से प्रतिशोध के लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत है। 20 वर्ष तक अमेरिका तोरा-बोरा की पहाड़ियों में खाक छानता रहा, उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान दोहरापन अपनाता रहा। अफगानिस्तान में अमेरिकी विफलता का कारण पाकिस्तान ही रहा।

बालेन शाह और नेपाल के युवा नेतृत्व का नया 'प्रशासनिक मॉडल'

नेपाल में 27 मार्च 2026 का दिन एक ऐसे युगांतकारी परिवर्तन के रूप में दर्ज हो गया है, जिसने न केवल हिमालयी राष्ट्र की दिशा बदल दी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए राजनीति का एक इतिहास लिख दिया। काठमांडू के शीतल निवास में जब 35 वर्षीय बालेंद्र शाह, जिन्हें दुनिया 'बालेन' के नाम से जानती है, ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो वह मात्र एक व्यक्ति का सत्तासीन होना नहीं था। वह उस 'जेन-ज़ी' विद्रोह की संवैधानिक परिणति थी, जिसने नेपाल के दशकों पुराने राजनीतिक सिंडिकेट और पारंपरिक दलीय व्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख दिया। यह जीत उस आक्रोश का परिणाम थी जो लंबे समय से नेपाल के युवाओं के मन में पुरानी पीढ़ी के नेताओं के प्रति पनप रहा था, जो सत्ता को 'म्यूजिकल चेयर' के खेल की तरह आपस में बदलते रहते थे।

इस क्रांति की नींव वास्तव में सितंबर 2025 में पड़ी थी, जब तत्कालीन के.पी. शर्मा ओली सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्मो पर प्रतिबंध लगाने का आत्मघाती निर्णय लिया। सरकार ने इसे नियमन का नाम दिया, लेकिन डिजिटल युग में पली-बढ़ी पीढ़ी के लिए यह उनकी अभिव्यक्ति की आजादी और आर्थिक संभावनाओं पर सीधा प्रहार था। देखते ही देखते काठमांडू की गलियां नारों और विरोध प्रदर्शनों से भर गई। यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से विकेंद्रीकृत और डिजिटल रूप से समन्वित था। जब सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया, जिसमें 77 लोगों की जान चली गई, तो शांतिपूर्ण विरोध एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में बदल गया। इसी जन-दबाव के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी, जिसने स्वतंत्र चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त किया। इन्ही घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि नेपाल की नई पीढ़ी अब केवल मूक दर्शक नहीं रही, बल्कि वह सत्ता परिवर्तन की निर्णायक शक्ति बन चुकी है।

5 मार्च 2026 को हुए आम चुनाव के परिणामों ने वह कर दिखाया जिसे नेपाल के राजनीतिक पंडित असंभव मान रहे थे। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 275 सीटों में से 182 सीटें जीतकर एक ऐसा प्रचंड बहुमत हासिल किया, जो नेपाल में 1999 के बाद किसी भी एकल दल को नहीं मिला था। इस 'चुनावी भूकंप' की सबसे बड़ी प्रतीकात्मक जीत झापा-5 निर्वाचन क्षेत्र में देखी गई, जहाँ बालेन शाह ने खुद पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को 50,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। पुरानी और स्थापित पार्टियाँ, जैसे नेपाली कांग्रेस और छक्क-रू इस कदर सिमट गई कि उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लगे। यह चुनाव परिणाम स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी के नेतृत्व के प्रति गहरे अविश्वास और नई, पारदर्शी एवं कार्य-उन्मुख राजनीति के प्रति जनता के अटूट उत्साह को दर्शाता था।

बालेन शाह का व्यक्तित्व इस नई राजनीति का केंद्रबिंदु है। 27 अप्रैल 1990 को जन्मे बालेन ने सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय पहचान एक ऐसे रैपर के रूप में मिली जिसके गीतों में व्यवस्था की खामियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ तीखा व्यंग्य होता था। 2022 में काठमांडू के मेयर के रूप में उनकी जीत ने पहली बार यह संकेत दिया था कि जनता अब पारंपरिक नेताओं से ऊब चुकी है। मेयर के रूप में उन्होंने कचरा प्रबंधन और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरह से तकनीक और 'लाइव वीडियो' का सहारा लिया, उसने उन्हें युवाओं का मसीहा बना दिया। इसके अलावा, बालेन का मधेश मूल से होना नेपाल के सामाजिक ताने-बाने के लिए भी एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि वे नेपाल के पहले मधेशी प्रधानमंत्री हैं। यह तराई क्षेत्र की उन लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का एक जवाब भी है, जिसमें खुद को सत्ता की मुख्यधारा से अलग-थलग महसूस करने की भावना निहित थी।

सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपनी सरकार को 'लीन गवर्नमेंट' या चुस्त शासन के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने नेपाल की उस पुरानी परंपरा को तोड़ दिया जहाँ गठबंधन के सहयोगियों को खुश करने के लिए दर्जनों मंत्रालयों का निर्माण किया जाता था। बालेन ने मात्र 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया, जिसमें कई मंत्रालयों का विलय कर दिया गया ताकि प्रशासनिक खर्चों में कटौती की जा सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया में गति आए। उनकी कैबिनेट में पहली बार 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व की संवैधानिक शर्त को पूरी तरह से लागू किया गया, जिसमें सोबिता गौतम और प्रतिभा रावल जैसी प्रखर महिला नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। साथ ही, डॉ. स्वर्णिम वागले जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री बनाकर सरकार ने यह संकेत दिया कि वह देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पूरी तरह गंभीर है।

बालेन शाह की सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी एजेंडा '2082 विजन' के रूप में सामने आया है। नेपाल की अर्थव्यवस्था वर्तमान में प्रेषण और आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जिसे बालेन एक उत्पादन-आधारित और आत्मनिर्भर मॉडल में बदलना चाहते हैं। इस विजन के तहत अगले पांच वर्षों में नेपाल की जीडीपी को 49 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने और प्रति व्यक्ति आय को 3,000 डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने 1.2 मिलियन उत्पादक रोजगार सृजन का वादा किया है ताकि उस 'ब्रेन ड्रेन' को रोका जा सके जिसके कारण हर दिन हजारों युवा खाड़ी देशों में मजदूरी के लिए जाने को मजबूर हैं। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से 30 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित करने और जलविद्युत उत्पादन को 15,000 मेगावाट तक ले जाने जैसे लक्ष्य इस सरकार की दूरगामी सोच को दर्शाते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके लिए नेपाल को लगातार दोहरे अंकों में विकास दर हासिल करनी होगी। प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ, बालेन सरकार के सामने न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। सुशीला कार्की के नेतृत्व वाले जांच आयोग की रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि 2025 के आंदोलनों के दौरान हुई मौतों के लिए पूर्व राजनीतिक और सुरक्षा नेतृत्व सीधे तौर पर जिम्मेदार था। बालेन ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने और दोषियों के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कदम उनके समर्थकों के बीच उनकी छवि को और मजबूत करेगा, लेकिन साथ ही इससे संसद में मौजूद विपक्ष के साथ उनके टकराव की संभावना भी बढ़ जाएगी। नेपाल जैसे देश में, जहाँ नौकरशाही और पुरानी व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं, बालेन के लिए इन सुधारों को धरातल पर उतारना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा।

विदेश नीति के मोर्चे पर भी नई सरकार एक 'साफ स्लेट' के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बालेन शाह, जिन्होंने पूर्व में मेयर रहते हुए भारत और चीन के साथ मानचित्र विवादों पर अत्यंत राष्ट्रवादी और कभी-कभी आक्रामक रुख अपनाया था, अब प्रधानमंत्री के रूप में एक संतुलित 'नेपाल फर्स्ट' नीति अपना रहे हैं। वे नेपाल को भारत और चीन के बीच के मात्र एक 'बफर स्टेट' के बजाय एक 'जीवंत सेतु' के रूप में विकसित करना चाहते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्वरित बधाई संदेश और बालेन की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह संकेत देती है कि दोनों देश ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को प्राथमिकता देने के इच्छुक हैं। वहीं, चीन के साथ संबंधों में सरकार किसी भी तरह के 'ऋण जाल' से बचते हुए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की पक्षधर है। बालेन का मानना है कि नेपाल की संप्रभुता सर्वोपरि है और विदेश नीति का एकमात्र पैमाना नेपाली जनता का आर्थिक हित होना चाहिए।

नेपाल का यह प्रयोग न केवल उस देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लोकतंत्रों के लिए एक सबक है। यह दर्शाता है कि जब पारंपरिक नेतृत्व जनता की आकांक्षाओं को समझने में विफल रहता है और भ्रष्टाचार को ही अपनी कार्य संस्कृति बना लेता है, तो नई पीढ़ी डिजिटल क्रांति के हथियारों के साथ स्वयं सत्ता का रुख मोड़ देती है। हालांकि, बालेन शाह के सामने चुनौतियां अपार हैं–चाहे वह नौकरशाही का प्रतिरोध हो, प्रेषण पर अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता हो या युवाओं की तुरंत नतीजे पाने की अधीरता। नेपाल में 1990 के बाद से 30 से अधिक सरकारें बदली हैं और किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इस अस्थिरता को समाप्त कर एक स्थिर और समृद्ध नेपाल का निर्माण करना ही बालेन शाह की वास्तविक सफलता होगी। फिलहाल, नेपाल ने एक नया स्वप्न देखा है, और हिमालय की चोटियों पर एक ऐसी पीढ़ी की गूँज सुनाई दे रही है जो अब केवल सवाल नहीं पूछती, बल्कि स्वयं समाधान बनने का साहस रखती है। यह जेन-ज़ी सरकार यदि सफल होती है, तो यह आधुनिक लोकतांत्रिक परिवर्तनों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी।

महेन्द्र तिवारी

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने गैस सिलेंडर की भारी कमी को लेकर उपजिलाधिकारी बिसवां को सौंपा मांग पत्र

बिसवां (सीतापुर) उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने गैस सिलेंडरों की भारी कमी को लेकर उपजिलाधिकारी बिसवां को मांग पत्र सौंपा। सफाई कर्मियों का कहना है कि नगर पालिका क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को लंबे समय से गैस सिलेंडर प्राप्त करने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संघ के अध्यक्ष बृजपाल वाल्मीकि, सफाई कर्मचारी पूरे दिन गैस एजेंसियों की लाइन में खड़े रहने के बावजूद सिलेंडर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनके दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं और शहर की सफाई व्यवस्था भी बाधित हो रही है। पदाधिकारियों ने मांग की कि सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारु रूप से कर सकें। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष बृजपाल वाल्मीकि, विजय वाल्मीकि, दीपक वाल्मीकि, रूपेश वाल्मीकि, अमित वाल्मीकि, रंजीत वाल्मीकि, महेंद्र सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे।

यूपी के 1.50 लाख बच्चों की चमकेगी किस्मत, योगी सरकार 1 अप्रैल से शुरू करने जा रही स्पेशल अभियान

1.5 लाख से अधिक ड्रॉपआउट बच्चों को जोड़ना लक्ष्य।

लखनऊ। प्रदेश में 1.50 लाख से अधिक ड्रापआउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए 'स्कूल चलो अभियान' का आगाज एक अप्रैल से किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए इस अभियान को प्राथमिकता के आधार पर चलाने को कहा है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, शैक्षिक सत्र 2026-27 में अभियान दो चरणों में संचालित होगा। पहला चरण एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक और दूसरा चरण एक जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। यू-डायस आंकड़ों के मुताबिक परिषदीय विद्यालयों में करीब 1,50,660 बच्चे ड्रापआउट श्रेणी में चिन्हित हैं। इन बच्चों की पहचान और नामांकन के लिए शारदा ऐप में 'ड्राप आउट स्टेट्स ' नाम से नया माड्यूल जोड़ा गया है। इसके जरिए शिक्षकों को ड्रापआउट बच्चों की सूची मिलेगी, जिनका नामांकन सुनिश्चित करना होगा। यदि कोई बच्चा पहले से ही विद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसकी स्थिति एप पर अपडेट करनी होगी। वहीं, यदि छात्र किसी अन्य स्कूल में नामांकित है तो संबंधित विद्यालय का यू-डायस कोड दर्ज करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के साथ इस प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।

उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में ओलावृष्टि से 244.23 हेक्टेयर फसल की हुई क्षति, किसानों को मिल रही सहायता

लखनऊ। प्रदेश में बीते कई दिनों तक खराब मौसम व ओलावृष्टि के 21 जिलों में कुल 244.23 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसका संज्ञान लेकर सभी जिलाधिकारियों को अन्नदाताओं के नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में आपदा से प्रभावित 286 किसानों को अब तक 13,34,217 रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। वहीं, अतिवृष्टि (अधिक वर्षा) के चलते स्थिति अधिक गंभीर रही। प्रदेश के 17 जिलों में 4053.11 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान कुल 14,207 किसान प्रभावित हुए, जिनमें से 9,992 किसानों को अब तक 4,47,24,779 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा, बीते दिनों 15 से 25 मार्च तक हुई बेमौसम भारी वर्षा से सहारनपुर के पांच गांवों में 11 हेक्टेयर फसल क्षति दर्ज की गई, जिसमें 44 किसान प्रभावित हुए हैं। ललितपुर की तीन तहसीलों में 1650.75 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल क्षति दर्ज की गई है, जिसमें कुल 3142 किसान प्रभावित हुए हैं। सरकार सभी जिलों में फसल क्षति का आकलन करा रही है, जिससे पात्र किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके।

स्टेशन का डीआरएम ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश

● अमृत भारत योजना के तहत प्रगति की समीक्षा, सुरक्षा व्यवस्था पर जताई नाराजगी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) सुनील कुमार वर्मा ने शनिवार को लालगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित इंजीनियरों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीआरएम शाम करीब 5:05 बजे स्टेशन पहुंचे और प्लेटफॉर्म सहित पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टिन शेड निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों की सुरक्षा व्यवस्था ठीक न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण स्थल को पूरी तरह घेरकर सुरक्षित बनाया जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और यात्रियों को असुविधा न उठानी पड़े। इसके अलावा उन्होंने पार्किंग और स्टेशन के बीच स्टेप ब्रेकवे बनाने के निर्देश भी दिए। वीआईपी लॉज का निरीक्षण करते हुए उन्होंने सोफों के कवर बदलने, पर्दों को ठीक करने और साफ-सफाई में सुधार के निर्देश दिए।

स्टेशन की पुरानी कैंटीन के संबंध में भी डीआरएम ने मातहतों को फाइल निकलवाकर समीक्षा करने को कहा और आवश्यकता पड़ने पर नया टेंडर जारी कर किसी अन्य को संचालन देने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिक अनिल कुमार यादव और पंकज कुमार ने पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव की मांग उठाई। साथ ही कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को पुनः संचालित करने की बात भी कही। इस पर डीआरएम ने आश्वासन दिया कि रेलवे बोर्ड से पत्राचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बातचीत में डीआरएम ने बताया कि यह उनका नियमित निरीक्षण है और पिछली बार की तुलना में कार्य में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म और बाहरी परिसर दोनों स्थानों पर तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। इस मौके पर डीओएम रजनीश श्रीवास्तव, सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी, जेई अभिषेक कुमार, स्टेशन अधीक्षक शंभूनाथ सोनकर समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

नेशनल पीजी कॉलेज के छात्रों ने सीखे आत्मनिर्भर के गुण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर, नेशनल पीजी कॉलेज, लखनऊ के बीएससी अंतिम वर्ष (2026) के लगभग 60 छात्र-छात्राओं ने आज चंद्रभानु गुप्ता कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बख्शी का तालाब में आयोजित शैक्षिक भ्रमण के दौरान कृषि एवं स्वरोजगार से जुड़े अनेक व्यावहारिक कौशलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह भ्रमण वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. अविजीत चैटर्जी तथा जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने मधुमक्खी पालन, ऑर्गेनिक खाद निर्माण, फूड प्रिजर्वेशन, बायोगैस, अदरक एवं पुष्पों के एक्सट्रैक्ट तैयार करना, फलों की जेली बनाना तथा औषधीय पौधों की खेती जैसे महत्वपूर्ण कौशलों को सीखा। चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के सह- आचार्य एवं आईक्यूएसी डायरेक्टर डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने मधुमक्खी पालन एवं जैविक कीट प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों को जैविक प्रबंधन, कीटों के पहचान के तरीके, गोबर गैस तथा इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी के विषय में भी जागरूक किया डॉक्टर सिंह ने बताया कि आज की वैश्विक समय के लिए गोबर गैस कि अहम आवश्यकता है। डॉ. हृदय नारायण तिवारी ने वर्मी कम्पोस्ट बनाने की विधि समझाई, जबकि डॉ. धीरेंद्र कुमार सिंह ने मुर्गी पालन एवं डेयरी प्रबंधन (पशुओं का भोजन, प्रजनन एवं रोग) पर विस्तार से जानकारी दी।

इसी क्रम में डॉ. दीपक पांडे, डॉ सुधाकर सिंह और डा एस सी चंदा ने मौसम विज्ञान से जुड़े उपकरणों–इवेपोरीमीटर, सॉइल टेम्परेचर डिवाइस, विंड वेन एवं मौसम वेधशाला–का परिचय कराया। भोजन उपरांत विद्यार्थियों को डॉ. दीप्ति श्रीवास्तव ने फूड प्रिजर्वेशन के अंतर्गत अदरक व फूलों के एक्सट्रैक्ट तथा फलों की जेली बनाने की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। इंजीनियर विपुल अग्रवाल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताते हुए फूड प्रोसेसिंग कर स्वरोजगार की ओर प्रेरित किया द्य

डॉ. योगेंद्र कुमार सिंह, प्राचार्य चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय ने वैल्यू एडेड कोर्स के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के अवसरों पर प्रकाश डाला। आपने बताया कि महाविद्यालय में वर्मी कंपोस्ट, मशरूम कलचर, मधुमक्खी पालन और फूड प्रोसेसिंग से संबंधित डिप्लोमा कोर्सेज भी संचालित किए जाते हैं जिसका छात्र-छात्राएं लाभ उठा सकते हैं और स्वावलंबी बन सकते हैं। इस शैक्षिक भ्रमण में जंतु विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अर्चना सिंह एवं वनस्पति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर अनुज सिंह भी उपस्थित रहे। भ्रमण का समापन राष्ट्रगान से हुआ

सम्पूर्ण कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। यह शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण अनुभव भी साबित हुआ।

अब 24 घंटे में यूपी के किसानों को मिलेगी रकम, राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव ने सभी जिलों के DM को दिए निर्देश

लखनऊ। राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा यू ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त फसल का आकलन कर प्रभावित किसानों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि दी जाए। शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने जिलाधिकारियों से प्रभावित परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप में संवाद स्थापित करने को भी कहा है। उन्होंने बताया कि राहत राशि के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। 15 मार्च से अब तक करीब 20 करोड़ रुपये विभिन्न जिलों को जारी किए जा चुके हैं। जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी तत्काल अतिरिक्त बजट की मांग कर सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि राहत राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1070 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि 15 से 28 मार्च के बीच प्रदेश में 17 लोगों की मौत, 11 पशुओं की मौत और सहारनपुर व ललितपुर में 1661.75 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है।

ढलान पर लुढ़की बोलेरो, बुजुर्ग महिला की मौत से गांव में मातम

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर कोटहा गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में वृद्ध महिला की जान चली गई। ढलान पर खड़ी एक बोलेरो अचानक लुढ़कने लगी और उसकी चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। गांव निवासी श्रीकृष्ण के अनुसार, शनिवार सुबह उनकी मां शिवनाथा (62) पत्नी बिन्दादीन सड़क पार कर पड़ोस के घर जा रही थीं। तभी ढलान पर खड़ी दिलीप पुत्र शिवमोहन की बोलेरो अचानक चल पड़ी। महिला संभल पातीं, इससे पहले ही वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की ओर से घटना की सूचना पुलिस को दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि बोलेरो में एक बालक सवार था और संभवतः हैंड ब्रेक हटने के कारण वाहन लुढ़क गया, जिससे यह हादसा हुआ। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। परिजनों के अनुरोध पर शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।

कार्यालय ग्राम पंचायत दिघुली विकासखंड हलिया मिर्जापुर

पत्रांकः मेमो/sBm रा वि अ. /के.वि.अ./ मनरेगा व अन्य मद /2026-27 दिनांक30/03/2026

अल्पकालीन निविदा

कार्यालय ग्राम पंचायत दिघुली विकासखंड हलिया जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (पेज-2) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंन्धन योजना वित्तीय वर्ष 2026 -27 मे निम्नलिखित कार्य आर जी एस ए /एस.बी.एम /15 वा वित्त/ पचंम वित्त/ मनरेगा की धनराशि से होना प्रस्तावित है7 निविदा दिनांक 30/03/ 2026 से 04/04/2026 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय पंचायत दिघुली मे निविदा शुल्क जमा कर प्राप्त करें एवं सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी दरें सील बंद लिफाफे में उक्त तिथियां को कार्यालय अवधि में जमा कर सकते हैं निविदा दिनांक 04/04/2026 को दिन में 11:30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय में गठित समितिके द्वारा खोली जाएगी जिसमें आपूर्ति की जाने वाली सामग्री ईट,गिट्टी, बालू, सरिया ,सीमेंट, ई -रिक्शा आयरन गेट ,पत्थर, मिट्टी ,आयरन सेट, इलेक्ट्रिक, एवं प्लंबरिंग सामग्री और अन्य सामग्री सहित आवश्यक सामग्री प्राक्कलन के अनुसार 1-नियम व शर्तें उपरोक्त सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकृत फार्मो द्वारा वेद प्रमाण पत्र दिखाने एवं जीएसटी की छाया प्रति संकलन करने पर ही निविदा डाली जाएगी सामग्री की आपूर्ति निश्चित समय सीमा में गुणवत्ता के अनुरूप किया जाना है तभी भुगतान संभव है निविदा के साथ 100 का स्टांप पेपर संलग्न करना आवश्यक है निविदा स्वीकृत और सुकृत करने का अधिकार गठित समिति में निहित होगा।

सुरेन्द्र कुमार
ग्राम प्रधान

गौरव कुमार
सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत कोठी धौकल सिंह विकासखंड हलिया मिर्जापुर

पत्रांकः मेमो/sBm रा वि अ. /के.वि.अ./ मनरेगा व अन्य मद /2026-27 दिनांक30/03/2026

अल्पकालीन निविदा

कार्यालय ग्राम पंचायत कोठी धौकल सिंह विकासखंड हलिया जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (पेज-2) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंन्धन योजना वित्तीय वर्ष 2026 -27 मे निम्नलिखित कार्य आर जी एस ए /एस.बी.एम /15 वा वित्त/ पचंम वित्त/ मनरेगा की धनराशि से होना प्रस्तावित है निविदा दिनांक 30/03/ 2026 से 04/04/2026 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय पंचायत कोठी धौकल सिंह मे निविदा शुल्क जमा कर प्राप्त करें एवं सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी दरें सील बंद लिफाफे में उक्त तिथियां को कार्यालय अवधि में जमा कर सकते हैं निविदा दिनांक 04/04/2026 को दिन में 11:30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय में गठित समितिके द्वारा खोली जाएगी जिसमें आपूर्ति की जाने वाली सामग्री ईट,गिट्टी, बालू, सरिया ,सीमेंट, ई -रिक्शा आयरन गेट ,पत्थर, मिट्टी ,आयरन सेट, इलेक्ट्रिक, एवं प्लंबरिंग सामग्री और अन्य सामग्री सहित आवश्यक सामग्री प्राक्कलन के अनुसार 1-नियम व शर्तें उपरोक्त सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकृत फार्मो द्वारा वेद प्रमाण पत्र दिखाने एवं जीएसटी की छाया प्रति संकलन करने पर ही निविदा डाली जाएगी सामग्री की आपूर्ति निश्चित समय सीमा में गुणवत्ता के अनुरूप किया जाना है तभी भुगतान संभव है निविदा के साथ 100 का स्टांप पेपर संलग्न करना आवश्यक है निविदा स्वीकृत और सुकृत करने का अधिकार गठित समिति में निहित होगा।

प्रेमा पाल
ग्राम प्रधान

गौरव कुमार
सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत बसकोप विकासखंड हलिया मिर्जापुर

पत्रांकः मेमो/sBm रा वि अ. /के.वि.अ./ मनरेगा व अन्य मद /2026-27 दिनांक30/03/2026

अल्पकालीन निविदा

कार्यालय ग्राम पंचायत बसकोप विकासखंड हलिया जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (पेज-2) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंन्धन योजना वित्तीय वर्ष 2026 -27 मे निम्नलिखित कार्य आर जी एस ए /एस.बी.एम /15 वा वित्त/ पचंम वित्त/ मनरेगा की धनराशि से होना प्रस्तावित है निविदा दिनांक 30/03/ 2026 से 04/04/2026 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय पंचायत बसकोप मे निविदा शुल्क जमा कर प्राप्त करें एवं सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी दरें सील बंद लिफाफे में उक्त तिथियां को कार्यालय अवधि में जमा कर सकते हैं निविदा दिनांक 04/04/2026 को दिन में 11:30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय में गठित समितिके द्वारा खोली जाएगी जिसमें आपूर्ति की जाने वाली सामग्री ईट,गिट्टी, बालू, सरिया ,सीमेंट, ई -रिक्शा आयरन गेट ,पत्थर, मिट्टी ,आयरन सेट, इलेक्ट्रिक, एवं प्लंबरिंग सामग्री और अन्य सामग्री सहित आवश्यक सामग्री प्राक्कलन के अनुसार 1-नियम व शर्तें उपरोक्त सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकृत फार्मो द्वारा वेद प्रमाण पत्र दिखाने एवं जीएसटी की छाया प्रति संकलन करने पर ही निविदा डाली जाएगी सामग्री की आपूर्ति निश्चित समय सीमा में गुणवत्ता के अनुरूप किया जाना है तभी भुगतान संभव है निविदा के साथ 100 का स्टांप पेपर संलग्न करना आवश्यक है निविदा स्वीकृत और सुकृत करने का अधिकार गठित समिति में निहित होगा।

सुरेश चन्द्र दुबे
ग्राम प्रधान

गौरव कुमार
सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत लोहरौह विकासखंड हलिया मिर्जापुर

पत्रांकः मेमो/sBm रा वि अ. /के.वि.अ./ मनरेगा व अन्य मद /2026-27 दिनांक30/03/2026

अल्पकालीन निविदा

कार्यालय ग्राम पंचायत लोहरौह विकासखंड हलिया जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (पेज-2) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंन्धन योजना वित्तीय वर्ष 2026 -27 मे निम्नलिखित कार्य आर जी एस ए /एस.बी.एम /15 वा वित्त/ पचंम वित्त/ मनरेगा की धनराशि से होना प्रस्तावित है निविदा दिनांक 30/03/ 2026 से 04/04/2026 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय पंचायत लोहरौह मे निविदा शुल्क जमा कर प्राप्त करें एवं सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी दरें सील बंद लिफाफे में उक्त तिथियां को कार्यालय अवधि में जमा कर सकते हैं निविदा दिनांक 04/04/2026 को दिन में 11:30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय में गठित समितिके द्वारा खोली जाएगी जिसमें आपूर्ति की जाने वाली सामग्री ईट,गिट्टी, बालू, सरिया ,सीमेंट, ई -रिक्शा आयरन गेट ,पत्थर, मिट्टी ,आयरन सेट, इलेक्ट्रिक, एवं प्लंबरिंग सामग्री और अन्य सामग्री सहित आवश्यक सामग्री प्राक्कलन के अनुसार 1-नियम व शर्तें उपरोक्त सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकृत फार्मो द्वारा वेद प्रमाण पत्र दिखाने एवं जीएसटी की छाया प्रति संकलन करने पर ही निविदा डाली जाएगी सामग्री की आपूर्ति निश्चित समय सीमा में गुणवत्ता के अनुरूप किया जाना है तभी भुगतान संभव है निविदा के साथ 100 का स्टांप पेपर संलग्न करना आवश्यक है निविदा स्वीकृत और सुकृत करने का अधिकार गठित समिति में निहित होगा।

संजय सिंह
ग्राम प्रधान

गौरव कुमार
सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत बरगड़ा विकासखंड हलिया मिर्जापुर

पत्रांकः मेमो/sBm रा वि अ. /के.वि.अ./ मनरेगा व अन्य मद /2026-27 दिनांक30/03/2026

अल्पकालीन निविदा

कार्यालय ग्राम पंचायत बरगड़ा विकासखंड हलिया जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (पेज-2) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंन्धन योजना वित्तीय वर्ष 2026 -27 मे निम्नलिखित कार्य आर जी एस ए /एस.बी.एम /15 वा वित्त/ पचंम वित्त/ मनरेगा की धनराशि से होना प्रस्तावित है निविदा दिनांक 30/03/ 2026 से 04/04/2026 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय पंचायत बढ़गड़ा मे निविदा शुल्क जमा कर प्राप्त करें एवं सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी दरें सील बंद लिफाफे में उक्त तिथियां को कार्यालय अवधि में जमा कर सकते हैं निविदा दिनांक 04/04/2026 को दिन में 11:30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय में गठित समितिके द्वारा खोली जाएगी जिसमें आपूर्ति की जाने वाली सामग्री ईट,गिट्टी, बालू, सरिया ,सीमेंट, ई -रिक्शा आयरन गेट ,पत्थर, मिट्टी ,आयरन सेट, इलेक्ट्रिक, एवं प्लंबरिंग सामग्री और अन्य सामग्री सहित आवश्यक सामग्री प्राक्कलन के अनुसार 1-नियम व शर्तें उपरोक्त सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकृत फार्मो द्वारा वेद प्रमाण पत्र दिखाने एवं जीएसटी की छाया प्रति संकलन करने पर ही निविदा डाली जाएगी सामग्री की आपूर्ति निश्चित समय सीमा में गुणवत्ता के अनुरूप किया जाना है तभी भुगतान संभव है निविदा के साथ 100 का स्टांप पेपर संलग्न करना आवश्यक है निविदा स्वीकृत और सुकृत करने का अधिकार गठित समिति में निहित होगा।

पानकली
ग्राम प्रधान

सचिव
सतोष कुमार

कार्यालय ग्राम पंचायत भिटहा विकासखंड हलिया मिर्जापुर

पत्रांकः मेमो/sBm रा वि अ. /के.वि.अ./ मनरेगा व अन्य मद /2026-27 दिनांक30/03/2026

अल्पकालीन निविदा

कार्यालय ग्राम पंचायत भिटहा विकासखंड हलिया जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (पेज-2) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंन्धन योजना वित्तीय वर्ष 2026 -27 मे निम्नलिखित कार्य आर जी एस ए /एस.बी.एम /15 वा वित्त/ पचंम वित्त/ मनरेगा की धनराशि से होना प्रस्तावित है निविदा दिनांक 30/03/ 2026 से 04/04/2026 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय पंचायत भिटहा मे निविदा शुल्क जमा कर प्राप्त करें एवं सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी दरें सील बंद लिफाफे में उक्त तिथियां को कार्यालय अवधि में जमा कर सकते हैं निविदा दिनांक 04/04/2026 को दिन में 11:30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय में गठित समितिके द्वारा खोली जाएगी जिसमें आपूर्ति की जाने वाली सामग्री ईट,गिट्टी, बालू, सरिया, सीमेंट, ई -रिक्शा आयरन गेट ,पत्थर, मिट्टी ,आयरन सेट, इलेक्ट्रिक, एवं प्लंबरिंग सामग्री और अन्य सामग्री सहित आवश्यक सामग्री प्राक्कलन के अनुसार 1-नियम व शर्तें उपरोक्त सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकृत फार्मो द्वारा वेद प्रमाण पत्र दिखाने एवं जीएसटी की छाया प्रति संकलन करने पर ही निविदा डाली जाएगी सामग्री की आपूर्ति निश्चित समय सीमा में गुणवत्ता के अनुरूप किया जाना है तभी भुगतान संभव है निविदा के साथ 100 का स्टांप पेपर संलग्न करना आवश्यक है निविदा स्वीकृत और सुकृत करने का अधिकार गठित समिति में निहित होगा।

अजय कुमार
ग्राम प्रधान

गौरव कुमार
सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत महुगढ़ विकासखंड हलिया मिर्जापुर

पत्रांकः मेमो/sBm रा वि अ. /के.वि.अ./ मनरेगा व अन्य मद /2026-27 दिनांक30/03/2026

अल्पकालीन निविदा

कार्यालय ग्राम पंचायत महुगढ़ विकासखंड हलिया जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (पेज-2) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंन्धन योजना वित्तीय वर्ष 2026 -27 मे निम्नलिखित कार्य आर जी एस ए /एस.बी.एम /15 वा वित्त/ पचंम वित्त/ मनरेगा की धनराशि से होना प्रस्तावित है निविदा दिनांक 30/03/ 2026 से 04/04/2026 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय पंचायत महुगढ़ मे निविदा शुल्क जमा कर प्राप्त करें एवं सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी दरें सील बंद लिफाफे में उक्त तिथियां को कार्यालय अवधि में जमा कर सकते हैं निविदा दिनांक 04/04/2026 को दिन में 11:30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय में गठित समितिके द्वारा खोली जाएगी जिसमें आपूर्ति की जाने वाली सामग्री ईट,गिट्टी, बालू, सरिया ,सीमेंट, ई -रिक्शा आयरन गेट,पत्थर, मिट्टी,आयरन सेट, इलेक्ट्रिक, एवं प्लंबरिंग सामग्री और अन्य सामग्री सहित आवश्यक सामग्री प्राक्कलन के अनुसार 1-नियम व शर्तें उपरोक्त सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकृत फार्मो द्वारा वेद प्रमाण पत्र दिखाने एवं जीएसटी की छाया प्रति संकलन करने पर ही निविदा डाली जाएगी सामग्री की आपूर्ति निश्चित समय सीमा में गुणवत्ता के अनुरूप किया जाना है तभी भुगतान संभव है निविदा के साथ 100 का स्टांप पेपर संलग्न करना आवश्यक है निविदा स्वीकृत और सुकृत करने का अधिकार गठित समिति में निहित होगा।

ग्राम प्रधान
विविध भारतीय पांडेय

सचिव
सदीप कुमार

संक्षिप्त खबरें

पुल की टूटी रेलिंग से बढ़ा हादसे का खतरा, मरम्मत की मांग तेज

श्रीभूमि: श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा क्षेत्र के पास पातियाला बटतला के सामने स्थित एक महत्वपूर्ण पुल की साइड रेलिंग कि हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। पुल की साइड रेलिंग टूट जाने से यहां हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पुल की रेलिंग हिस्से काफी कमजोर हो चुके हैं। इस मार्ग से रोज़ाना बड़ी संख्या में वाहन और पैदल यात्री गुजरते हैं, जिनमें स्कूल-कॉलेज के छात्र, मरीज, बुजुर्ग और आम नागरिक शामिल हैं। ऐसे में यह स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित लोक निर्माण (PWD) विभाग को सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आरोप है कि अधिकारियों ने केवल औपचारिकता निभाते हुए टूटे हिस्से पर लाल फीता बांध दिया है, जिससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने और पुल की टूटी रेलिंग की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की नींव को मिलेगी मजबूती, पानी से होगा बचाव

स्मारकों की नींव में पानी जाने से रोका जाएगा।

एएसआई दिल्ली के 174 स्मारकों का संरक्षण करेगा।

मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था सुधारी जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली के सभी ऐतिहासिक गेटों को मजबूती दी जाएगी । इसके लिए इनके संरक्षण कार्य से लेकर इनकी मजबूती बनाए रखने के लिए काम किया जाएगा। जिसके तहत ऐसे गेटों के आसपास जल निकासी का उचित प्रबंध किया जाएगा ताकि उनकी नीव में पानी पहुंचकर इनका नुकसान ना करे। दिल्ली गेट स्मारक से यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। दिल्ली भर में ऐसे स्मारकों की पहचान करी जा रही है, जिनकी नीव में पानी भरता है और बरसाती पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है।

दिल्ली में कितने स्मारक हैं?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पास दिल्ली में 174 स्मारक हैं। इनमें से कई जर्जर हालत में हैं, इन्हें बचाने के लिए पिछले सालों में भी काम किया गया है। इनमें बेगमपुरी कि वह मस्जिद भी शामिल है जिसकी नीव में कई वर्षों से पानी जा रहा था। कुछ साल पहले इसके चारों ओर बंद पड़ी नालियों को खोलकर पानी की निकासी की व्यवस्था बेहतर की गई है। स्मारक को बचाने के लिए कुछ संरक्षण कार्य भी किया गया है। इसी की तर्ज पर दिल्ली गेट स्मारक में भी पिछले कुछ माह से काम चल रहा है। जिसके तहत स्मारक में जरूरी संरक्षण कार्य पूरा कराया गया है। इसके अलावा नीव में जाने वाले पानी को रोकने के लिए पाइपलाइन डालकर व्यवस्था को इस तरह बनाया जा रहा है। मकसद यह है कि मानसून के दौरान इसकी नीव में पानी न जाए और बाहर निकल जाए। दरअसल यह समस्या एएसआइ के कई स्मारकों में बनी हुई है।

बरसाती पानी को रोकने का होगा इंतजाम

एएसआई ने इसे देखते हुए अब उन सभी स्मारकों को लेकर योजना तैयार की गई है। जिसके तहत सभी ऐसे स्मारकों की पहचान कर उनकी नीव में जाने वाले बरसाती पानी को रोकने का इंतजाम किया जाएगा। इस कार्य को मानसून से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही एएसआई ने मानसून से पहले सभी स्मारकों में जल निकासी सहित उन सभी इंतजाम को बेहतर करने का निर्देश दिया है कि जिन में जल निकासी या बरसाती जल निकासी को लेकर कुछ अड़चन है। एएसआइ के पूर्व अधिकारी कहते हैं कि स्मारकों को बचाने के लिए संरक्षण कार्य के साथ-साथ उनकी नीव को बचाना भी जरूरी है। मानसून के दौरान पानी नीव में इकट्ठा होता है जो कहीं ना कहीं स्मारकों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है।

डेटिंग ऐप के जरिए अपहरण और लूट का खुलासा: 5 आरोपी गिरफ्तार

● कालकाजी क्षेत्र में हुई वारदात को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझाया, दो कारें और मोबाइल बरामद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने कालकाजी थाना क्षेत्र में हुए अपहरण व लूट के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई दो कारें, पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं और आरोपियों के बैंक खातों में हुई लेनदेन की जानकारी भी खंगाली है।पुलिस के अनुसार, 25 मार्च 2026 को पीड़ित अनुरूप नारूला को एक डेटिंग ऐप '3स्न' के जरिए 'स्न्द्वद्गह्वह्ल4' नाम की प्रोफाइल से संपर्क किया गया। मुलाकात के लिए उसे नेहरू प्लेस बुलाया गया, जहां पहुंचने पर महिला के साथ मौजूद तीन युवकों ने उस पर हमला कर उसे जबरन एक कार में बैठा लिया। आरोपियों ने पीड़ित को गला दबाकर बेहोश कर दिया और डराकर उससे करीब 7 लाख रुपये यूपीआई, एटीएम और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ट्रांसफर करा लिए। बाद में उसे धमकी देकर नेहरू प्लेस इलाके में ही छोड़ दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व निरीक्षक आर.एस. डागर ने किया और इसमें कई अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), ओएसआईएनटी इनपुट, एएनपीआर और फास्टैग डेटा का विश्लेषण किया, जिसके आधार पर संदिग्ध वाहनों और आरोपियों की पहचान की गई।इसके बाद पुलिस ने एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान आरोपी ऋषभ राघव को एक कार सहित पकड़ा गया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अन्य आरोपी–नबोजीत डे, संजय उर्फ जॉय और हरलीन कौर उर्फ जेनी को मालवीय नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके साथ ही एक अन्य आरोपी साहिल चौहान को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हरलीन कौर डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। तय समय और स्थान पर मिलने के लिए बुलाने के बाद उसके साथी मिलकर पीड़ितों को लूटते थे। यह गैंग सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देता था।

गिरफ्तार आरोपियों में नबोजीत डे जिम ट्रेनर है, जबकि उसका भाई संजय वेटरनरी डिप्लोमा कर रहा है। ऋषभ पेशे से कैब ड्राइवर है और हरलीन कौर मुख्य रूप से इस गिरोह में लोगों को फंसाने का काम करती थी। सभी आरोपियों का अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य संभावित पीड़ितों तथा नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सतर्क रहने की सलाह दी।

पूर्वी दिल्ली के शकूरपुर में अर्थमूवर से कुचलकर युवक की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के शकूरपुर इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक युवक की अर्थमूवर से कुचलकर मौत हो गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, 34 साल का हुसैन सुबह 7:00 बजे अपने काम पर जाने के लिए घर से निकला था तभी शकूरपुर इलाके में एक अर्थमूवर ने उसे कुचल दिया। उसके बाद भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान आगे जाकर एक गाड़ी को भी टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ड्राइवर को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तरी पश्चिमी जिला के सुभाष प्लेस थाना क्षेत्र में आज सुबह 7 बजे की है। पुलिस ने अर्थमूवर जब्त कर आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया। मृतक हुसैन के परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। मजदूरी करके पूरी परिवार का गुजारा करते थे। आज सुबह वह अपने घर से काम पर जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार अर्थमूवर ने उन्हें टक्कर मार दी। परिवार में अकेला कमाने वाला था। इस हादसे के बाद से पत्नी ममता का रो रोकर बुरा हाल है। आरोपित के खिलाफ सख्त सजा की मांग कर रही है।

क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ की बैठक में विकास कार्यों के लिए 25.75 करोड़ का बजट पास

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। ब्लाक शोहरतगढ़ परिसर में शनिवार को क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक ब्लाक प्रमुख प्रीती यादव की अध्यक्षता में हुई। जिसमें में सर्वसम्मति से अगले वित्तीय वर्ष 2026- 27 में विकास कार्यों के लिए 25.75 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्य क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधानों ने विकास कार्य के लिए क्षेत्र के विकास कार्य के लिए प्रस्ताव भी दिए। बीडीओ चंद्रभूषण तिवारी ने पूर्व की कार्यवाही व विकास कार्यों के बारे में चर्चा सदन के समक्ष किया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधित संचालित योजनाओं की जानकारी सदन में रखी।

ब्लॉक प्रमुख शोहरतगढ़ प्रीति यादव ने कहा कि सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र से संबंधित कार्यों संबंधित प्रस्ताव को समय से उपलब्ध करा दें ताकि कार्य योजनाओं में सम्मिलित कर विचार किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के विकास के लिये अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर विकास कार्य को गति प्रदान किया गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जन समुदाय के सहयोग से अन्य जरूरी शेष कार्यों को भी पूरा कराने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि जनता की ओर से चुने गए सभी जनप्रतिनिधि व शासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी जब मिलकर काम करँगे, तभी गांव व क्षेत्र का बेहतर विकास होना संभव है। ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों के द्वारा विकास कार्य में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। ब्लॉक प्रमुख ने यह भी कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में जिन विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति नहीं रही है , उनके खिलाफ उच्चाधिकारियों को पत्र देकर आवश्यक कार्यवाही के लिये अवगत कराया जायेगा। कार्यक्रम को प्रधान संगठन जिलाध्यक्ष डॉ पवन मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष जफर आलम , प्रमुख प्रतिनिधि अमित यादव, विक्रम यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विभाग से जुड़ी योजनाओं व उनकी प्रगति के बारे में सदन में चर्चा किया। इस दौरान सूर्यप्रकाश पांडेय, नर्वदेश्वर मणि त्रिपाठी, शिवशंकर चौधरी, राजीव सिंह, मोहनलाल, मुस्ताक अहमद, सुनील सिंह, मंजू, संजय पटेल, रामदास, सुभाष यादव आदि लोग मौजूद रहे।

भारत का 5000 टन डीजल पहुंचा बांग्लादेश, गदगद हुए तारिक रहमान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर साफ दिखाई देने लगा है। जहां ग्लोबल ऑयल सप्लाई में आई रुकावटों के चलते दुनिया के कई देशों की मुश्किलें बढ़ गई और इस समय भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी गंभीर ईंधन संकट का सामना कर रहा है और ऐसे मुश्किल हालात में बांग्लादेश की मदद के लिए भारत ने आगे बढ़कर कदम उठाया। दरअसल खबर सामने आई है कि भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की अतिरिक्त आपूर्ति भेजी है। इसके साथ ही हाल के दिनों में भारत से बांग्लादेश को कुल 15,000 टन डीजल पहुंचाया जा चुका है। बांग्लादेश को जा रही आपूर्ति आसाम में स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी से भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए की जा रही है जो सीधे बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो तक डीजल पहुंचाती है। सूत्रों के मुताबिक भारत की ओर से यह आपूर्ति यहीं नहीं रुकने वाली बल्कि 28 मार्च को भी 6000 टन और डीजल भेजा जाएगा। वहीं अप्रैल महीने के लिए भारत ने 400 टन डीजल सप्लाई करने का प्रस्ताव बांग्लादेश को दिया जिसे बांग्लादेश ने मंजूर कर लिया है। माना जा रहा है कि इससे बांग्लादेश के बिजली उत्पादन और परिवहन व्यवस्था पर पड़े भारी दबाव को काफी हद तक कम किया जाएगा। दरअसल बांग्लादेश की सालाना डीजल मांग लगभग 40 लाख टन है और यह पूरी तरह आयात पर निर्भर है। ऐसे में वैश्विक संकट का सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर और आम जनजीवन पर पड़ा है। अब भारत की ओर से लिए गए इस कदम के कई अहम मायने सामने आ रहे हैं। जहां साल 2024 में बांग्लादेश में आए राजनीतिक बदलाव के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बेहद खराब दौर से गुजरना पड़ा है।

दोनों देशों के बीच कई ऊर्जा समझौतों की समीक्षा कर दी गई थी और कुछ परियोजनाएं बिल्कुल ठप पड़ गई थी। लेकिन हाल ही में हुए चुनाव और सत्ता परिवर्तन के बाद वापस से हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां नई सरकार के साथ भारत के संबंध में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और मौजूदा डीजल की आपूर्ति को दोनों देशों के बीच फिर से मजबूत होते हुए सहयोग और भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच यह पहल ना केवल बांग्लादेश के लिए राहत की खबर है बल्कि क्षेत्ररता और सहयोग को भी मजबूत करने की एक खबर है। भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसियों की मदद करता आ रहा है और संकट की स्थिति में भारत का ये कदम पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। फिलहाल सभी की नजरें आने वाले महीनों पर टिकी है। जहां यह देखना अहम होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच का सहयोग किस दिशा में आगे बढ़ता है। वहां की नई सरकार के आने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध किस दिशा में जाते हैं।

दिल्ली में डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद, नाबालिग की चाकू मारकर हत्या

बाहरी दिल्ली। दिल्ली के रानी बाग इलाके में शुक्रवार की देर रात एक शादी समारोह के दौरान गाना बजाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चाकूबाजी की इस घटना में साढ़े 17 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने कुछ नाबालिगों समेत सात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात शादी समारोह में दो पक्षों के युवकों के बीच अपनी-अपनी पसंद का गाना डीजे पर चलाने को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और एक पक्ष ने चाकू से हमला कर दिया।

सीने में लगे चाकू से घायल हुआ फिर अस्पताल में तोड़ा दम

हमले में नाबालिग के सीने में चाकू लगा, जबकि उसके साथी सनी को कमर के नीचे चोट आई। दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एसीपी, एसएचओ और क्राइम टीम मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर संदिग्धों की पहचान की गई।

रोहिणी के रहने वाले हैं मृतक

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक और घायल युवक रोहिणी के नाहरपुर इलाके के रहने वाले हैं। मृतक मोटर मैकेनिक का काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देर रात तक चली छापेमारी में कुछ नाबालिगों समेत सात लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। फरार अन्य आरोपितों का पुलिस पता लगा रही है।

ड्रग सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई: साउथ-ईस्ट जिले की एएनएस टीम ने 10 लाख की एमडी के साथ दो तस्करों को दबोचा

● गुरुद्वारा रोड तैमूर नगर में घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपी, सप्लाई चेन की जांच जारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। 28 मार्च। नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड (एएनएस) ने संगठित ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत 99.25 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई को ड्रग तस्करी के नेटवर्क पर करारा प्रहार माना जा रहा है।पुलिस के अनुसार, एएनएस टीम को 27 मार्च 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि तैमूर नगर इलाके में ड्रग्स की बड़ी खेप पहुंचाई जाने वाली है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर विष्णु दत्त के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें कई अनुभवी पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गुरुद्वारा रोड स्थित एसपीए गेट नंबर-1 के पास घेराबंदी कर दी और संदिग्ध वाहनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक मारुति एक्सएल-6 कार और एक टीवीएस एनटॉर्क स्कूटी को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर दोनों वाहनों में सवार आरोपी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सतर्क टीम ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दोनों के पास से कुल 99.25 ग्राम एमडी बरामद हुई। पूरी कार्रवाई को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए दस्तावेजित किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कार्तिक मिश्रा (30) निवासी तैमूर नगर और विशाल (20) निवासी गोविंदपुरी के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि कार्तिक मिश्रा इस पूरे ड्रग नेटवर्क का मुख्य संचालक है और वह कालकाजी क्षेत्र में 'ईगल आई कैफे' नाम से एक कैफे चलाता है। वहीं विशाल उसका करीबी सहयोगी है, जो ड्रग्स की सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालता था।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी

कार्रवाई जारी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहे हैं, लेकिन ड्रग्स के इस नेटवर्क से जुड़कर उन्होंने अवैध गतिविधियों में कदम रखा।एएनएस टीम अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि ड्रग्स की सप्लाई कहां से हो रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से राजधानी में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट की कमर तोड़ने में मदद मिलेगी।पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और समाज को इस खतरे से मुक्त करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

जिले केमहादेवा में गूंजेगा 'राम नाम महामंत्र', 28 मार्च से पांच दिवसीय भव्य आयोजन

● सनातन धर्म की अलग जगाने के लिए राम नाम कथा का शुभारंभ जिसके मुख्य वक्ता अवधेश जी महाराज के मुखारविंद से राम नाम का होगा आगाज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। बस्ती जिले के विकास क्षेत्र बनकटी के महादेवा चौराहे पर पहली बार 'राम नाम महामंत्र' के विशाल धार्मिक आयोजन का भव्य शुभारंभ 28 मार्च से होने जा रहा है। पांच दिवसीय संगीतमय कथा एवं सवा करोड़ श्रीराम नाम जप का यह आयोजन राष्ट्रीय संत अवधेश जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा।आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम 28 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अयोध्या धाम से आए संत-महात्माओं द्वारा संगीतमय राम कथा का वाचन किया जाएगा तथा अखंड कीर्तन और राम नाम जप का क्रम लगातार चलता रहेगा।

कार्यक्रम का समापन 2 अप्रैल 2026 को भंडारे के साथ होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन समिति ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 'राम नाम महामंत्र' (रघुनंदन राघव राम हरे सियाराम हरे) के जप में सहभागी बनें और कम से कम दो से चार घंटे का समय देकर पुण्य लाभ अर्जित करें।

इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोगों को आयोजक, संयोजक एवं व्यवस्था समिति में शामिल किया गया है। आयोजन स्थल राम मड़ैया, सूर्या क्लीनिक महादेवा में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

जिला वृक्षारोपण,पर्यावरण, गंगा समिति की बैठक सीडीओ की अध्यक्षता में सम्पन्न

● जैविक खेती व गंगा संरक्षण पर अधिकारियों को मिले निर्देश

● समीक्षा बैठक में पर्यावरण संरक्षण एवं गंगा स्वच्छता पर जोर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

भदोही 28 मार्च 2026:-जिलाधिकारी शैलेष कुमार के मार्गदर्शन में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोबिन्द शुक्ल की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति,गंगा समिति, प्रदूषण ,पर्यावरण के कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक कलेक्टेऊट सभागार में सम्पन्न हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जब पर्यावरण सुरक्षित होगा, तभी हम लोग भी सुरक्षित होंगे, जो पेड़ लगाये गये है उन पेड़ों का बचाव का प्रयास हम करेंगे संकल्प लें। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण करने हेतु दिए गए प्रारूप में डाटा फीड कर उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया। पौधों के रखरखाव एवं अन्य बिंदुओं पर बल दिया गया।

जिला पर्यावरण समिति के अंतर्गत जनपद में उत्पन्न हो रहे गीला कचरा के उपचार हेतु उपलब्ध वेट कंपोस्टिंग पिट की कार्यात्मक स्थिति की समीक्षा की गई। जनपद में उत्पन्न हो रहे प्लास्टिक अपशिष्टों को रिसायकल एवं प्रबन्धन (सड़क निर्माण, ऊर्जा निर्माण इत्यादि में) हेतु की जा रही कार्यवाही की गयी। समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में ठोस अपशिष्ट ट्रांसफर स्टेशन, डम्पिंग साईट क्षमता एवं कार्यात्मक स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट पर बल दिया गया। जनपद में उत्पन्न हो रहे कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट के उचित निस्तारण एवं प्रबन्धन हेतु की जा रही कार्यवाही की गयी। जनपद में उत्पन्न हो रहे ठोस अपशिष्ट के उपचार एवं वैज्ञानिक प्रबन्धन (वेस्ट टू कम्पोस्ट एवं वेस्ट टू एनर्जी) हेतु की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की गयी। जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के फण्टलाईन स्टाफ के कार्यात्मक क्षमता की अभिवृद्धि हेतु किये जा रहे कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। जनपद में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग हेतु की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की गयी।

जिला गंगा समिति के अन्तर्गत गंगा किनारे स्थित शव दाह गृह का संचालन विद्युत से किया जाय जिससे नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकें। गंगा ग्रामों में किसानो को जैविक खेती हेतु प्रेरित किया जाय तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति आम जनमानस में जन जागरूकता हेतु अभियान चलाया जाय। जनपद में संचालित समस्त डाईग प्लान्ट से निसृत हो रहें तरल अपशिष्ट की गुणवत्ता की जांच की जाय साथ ही गुणवत्ता मानक अनुरूप न होने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायें। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोबिन्द शुक्ल ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बढ़ते खतरे के जनपदवासियों को जागरूक करते हुए सीडीओ ने जनपदवासियों से कपड़े वाले थैले या बायोडिग्रेबल थैले में समान लेने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी विवेक यादव, एसीएमओ डॉ ओपी शुक्ला, डीआईओ डॉ पंकज कुमार एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण, संभ्रांत नागरिकगण उपस्थित रहे। जिला सूचना कार्यालय भदोही द्वारा प्रसारित।

आरसीबी बनाम एसआरएच: आईपीएल 2026 के पहले मैच में काली पट्टी पहनकर उतरी आरसीबी और हैदराबाद टीम

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आज, 28 मार्च से आगाज हो गया है। पहले मैच में गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। ऐसे में ईशान किशन की कप्तानी वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी है। मुकाबले में आरसीबी और हैदराबाद के प्लेयर काली पट्टी पहनकर मैदान पर उतरे हैं। ऐसे में सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।

11 लोगों की गई थी जान

आरसीबी ने 17 साल का सूखा खत्म करते हुए आईपीएल 2025 का खिताब अपने नाम किया था। पिछले सीजन के फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्?स को मात दी थी। इसके बाद बेंगलुरु में विक्ट्री परेड हुई थी, इस दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी।

इन 11 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आरसीबी और हैदराबाद के सभी प्?लेयर आज अपनी बांह पर ब्लैक आर्मबैंड पहनकर मैदान में उतरे हैं। इतना ही नहीं मैच से पहले उन 11 फैंस को श्रद्धांजलि दी गई। उनके लिए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। बीसीसीआई ने ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं करने का फैसला लिया।

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेइंग इलेवन

विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, रजत

पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा।

इम्पैक्ट प्लेयर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: देवदत्त पडिक्कल, जैकब बेथेल, रसिख सलाम डार, कनिष्क चौहान, वेंकटेश अय्यर।

सनराइजर्स हैदराबाद: शिवांग कुमार, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड पायने, स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन।